



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 256 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

8 मार्च, 2019

विषय:- एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (JUUIP) के अंतर्गत 75266.22 लाख रु० की लागत पर तकनीकी स्वीकृत राँची शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज-2, पैकेज-A) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- SUDA/EAP/Ranchi-WSS(2A)/02/2019/UDHD-1145(अनु०) -- नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में राँची नगर निगम क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति में सुधार एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए राँची शहरी जलापूर्ति योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का निर्माण तीन चरणों में किया गया है। तीन अलग-अलग चरणों में DPR तैयार करने का मुख्य कारण परियोजना का अलग स्रोतों से प्रस्तावित वित्तपोषण एवं आच्छादन क्षेत्र में भूमि की सुलभ उपलब्धता है। प्रस्तावित तीनों चरणों में से फेज-1 परियोजना का कार्यान्वयन "अमृत" योजना अंतर्गत किया जा रहा है। इस क्रम में परियोजना के फेज-2, पैकेज-A की परियोजना का सूत्रण किया गया है। इस योजना का वित्तपोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा संपोषित झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (JUUIP) के अंतर्गत किया जाएगा।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा संचालित हो रही झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (JUIIP) के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा दिनांक 21.11.2017 को हुई स्क्रीनिंग कमिटी की 77वीं बैठक में उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु झारखण्ड राज्य को 458 मिलियन डॉलर के वित्तीय सहायता की अनुशंसा के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) को अग्रसारित किया गया है।

(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग का पत्र अनुलग्नक - 1 पर संलग्न)।

3. चूंकि इस परियोजना की लागत राशि 75266.22 लाख रु० अर्थात् 105.45 मिलीयन डॉलर है, जो 40 मिलीयन डॉलर से अधिक है, अतः ADB के दिनांक 23 अगस्त 2013 के पत्र एवं ADB द्वारा प्रकाशित Project Administration Instruction (PAI) 3.03, दिनांक 13.08.2014 के आधार पर इस परियोजना के Civil Work Contract के नए threshold (USD 40 million) के तहत International Competitive Bidding (ICB) के लिए बने Standard Bidding Document के अनुसार ही निविदा दस्तावेज तैयार कर निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। (ADB द्वारा संयुक्त सचिव, एमआइ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग, को भेजे गए पत्र की प्रति अनुलग्नक-2A एवं ADB द्वारा प्रकाशित Project Administration Instruction 3.03, दिनांक 13.08.2014 के परिशिष्ट-2 की प्रति अनुलग्नक - 2B पर संलग्न)

4. उक्त के आलोक में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माह जून-2011 में प्रकाशित हस्तक (Handbook) में Project Preparation & Loan Negotiations with Multilateral Development Banks (MDBs) की दिशा-निर्देशिका के कंडिका-20 में अंकित निर्देशों के आधार पर ADB के Standard Bid Document के अनुरूप प्रस्तावित परियोजना के लिए संवेदक के चयन हेतु Standard Bid Document (SBD) तैयार किया गया है जिसके आधार पर निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित हस्तक के भाग अनुलग्नक-3 पर संलग्न)। उक्त दिशा-निर्देशिका की प्रसंगाधीन कंडिका के आलोक में परियोजना हेतु तैयार SBD के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार जुड़को लि० के निदेशक मंडल के पास होगा।

5. अमृत योजना अंतर्गत कार्यान्वित जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के अंतर्गत 1,06,935 घरों को लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन से आच्छादित क्षेत्र के कुल 60,932 घरों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

6. इस परियोजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24x7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

7. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित हैं :-

Components	Details
Source	Getalsud Dam
Water Treatment Plant	213 MLD
Under Ground Reservoir (UGR) – 1 No.	28214 KL
Elevated Storage Reservoirs (ESR) – 12 Nos.	2450 KL – 2 Nos., 2950 KL – 1 No., 1700 KL – 1 No., 2400 KL – 1 No., 1550 KL – 1 No., 1100 KL – 2 Nos., 2250 KL – 1 No., 2350 KL – 1 No., 650 KL – 1 No., 2050 KL – 1 No.
House service connections with meters	60,932 Nos
Raw Water Rising main	0.6 Kms
Clear Water Rising main	60 Kms
Distribution Network	445 Kms.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	Up to ESR outlets.

8. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :-

Sl. NO.	DESCRIPTION	TOTAL COST (Rs.)
1	Estimate of Sub Station at Rukka	67,54,458.00
2	Estimate of Civil works at Old Intake, Rukka	1,39,75,397.00
3	Estimate of E & M at Intake Well	4,09,16,821.28
4	Estimate of New Water Treatment Plant of 213 MLD	23,39,10,698.00
5	Additional Clear Water Storage Sump with Pump House in WTP, Capacity - 2000 KL	62,26,392.70
6	Estimate of E & M at WTP	16,81,93,504.92
7	Estimate of Raw & Clear Water Rising Main	1,54,62,32,747.00
8	Estimate of Under Ground Reservoir with Pump house. (1 nos.) UGR-4, Capacity - 28,214 KL	5,55,34,926.70
9	Estimate of E & M at UGR	6,89,36,759.16
10	Estimate of Distribution System (13 Sub Zones) Sub Zone - 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19 & 21	85,59,35,016.00
11	Estimate of Elevated Service Reservoirs (12 nos.)	13,46,08,279.46
12	Estimate of NH Crossing & Ring Road Crossings	1,53,39,866.00
13	House Service Connection with meter (60932 nos.)	24,35,45,204.00
14	Compound Wall with Gate for 12 nos. of Prop. ESR & 1 no. Proposed UGR	92,02,336.00
15	Approach Road for 9 nos. of Prop. ESR & 2 nos. Prop UGR	12,77,114.00
16	Instrumentation, Control & Automation (ICA) for SCADA	8,78,69,287.00
17	EMP and Environmental Monitoring	1,04,52,821.00
18	River/Major Nallah crossings (6 nos.)	2,95,00,000.00
19	Total Cost (A) :-	3533997006.76
20	Add GST@18% on A	42,40,79,640.81
21	Sub Total (A1)	3,95,80,76,648.00
22	Add 1% For Labour Cess On Sub Total (A1)	3,95,80,766.47
23	Total	3,99,76,57,414.05
24	Provisional Sum @ 3% of A1	11,87,42,299.44
25	Add JUIDCO Charges on Gross Total (योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	8,15,80,766
26	Add Consultancy (0.97%) and PMC Charges (2.06%) on Sub Total	11,99,29,722.00
27	Provision of Way leave & other charges for NOC from Railway	70,00,000.00
28	Provision of Departmental charges for NOC from NHAI/RCD/JARDCL	1,00,00,000.00
29	Total Capex	433,49,10,201.49
30	Operation And Maintenance for 1st Year excluding annual repair charges.	49,47,36,372.00
31	Operation And Maintenance for 2nd Year including annual repair charges	56,72,48,333.20
32	Operation And Maintenance for 3rd Year	62,39,73,166.52
33	Operation And Maintenance for 4th Year	68,63,70,483.17
34	Operation And Maintenance for 5th Year	75,50,07,531.49
35	Comprehensive 5 Year O&M Cost of Centralized SCADA Center	1,70,01,108.00
36	Total Cost :-	3,14,43,36,994.38
	Total O & M excluding Power Cost (B)	36,10,90,165.00
37	Add GST 12 % on B	4,33,30,820.00
38	Sub Total (B1)	40,44,20,985.00
39	Add 1% For Labour Cess On Sub Total (B2)	40,44,209.85
	Add Power Cost	278,32,46,829.00
40	Total Opex	319,17,12,023.65
41	Total (Capex + Opex)	752,66,22,225.52
42	Say	752,66,22,000.00

9. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 43349.10 लाख रु० है और 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 31917.12 लाख रु० है अर्थात् कुल प्राक्कलन 75266.22 लाख रु० है। CAPEX का 70% एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX की राशि में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आगामी पाँच वर्षों में अनुमानित विद्युत खपत के वहन का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना के परिचालन एवं रख-रखाव की राशि (OPEX) में से बिजली के बिल का भुगतान का वहन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा अतः उक्त का वहन राज्य योजना मद से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के कारणवश OPEX का दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। OPEX के प्रथम भाग का 70% ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण के रूप में एवं 30% राज्यांश के रूप में देय होगा। OPEX का द्वितीय भाग (बिजली का बिल) को राज्य मद से वहन करना होगा जो संबंधित नगर निकाय को विद्युत की वास्तविक की खपत के आधार पर प्राप्त विपत्र के आधार पर देय होगा।

10. उक्त के आलोक में प्रस्तावित परियोजना का वित्तपोषण निम्नवत किया जाएगा :-

(Amount in Lakhs)

	Approved Project Cost (CAPEX+OPEX)	Part of JUIIP aided by ADB		Non-JUIIP Part, to be paid by ULB
		ADB Share (70%)	State Share (30%)	
CAPEX	43349.10	30344.37	13004.73	-
OPEX	31917.12	2859.26	1225.39	27832.47
Total Project Cost (A+B)	75266.22	33203.63	14230.12	27832.47

11. उपर्युक्त कंडिका - 10 में अंकित तालिकानुसार JUIIP के अंतर्गत आने वाली राशि (Part of JUIIP aided by ADB) में से ADB Share+State Share का कुल योग) अर्थात् कुल 47433.75 लाख रु० एवं Non- JUIIP भाग की राशि अर्थात् 27832.47 लाख रु० का वहन राज्य योजना अंतर्गत “मांग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग), मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-67-बाह्य संपोषित योजनाओं हेतु अनुदान (ई०ए०पी०), विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) विपत्र कोड- 48S221780796670679” से किया जाएगा। तदुपरांत JUIIP अंतर्गत हुए व्यय 70% राशि की मांग केन्द्र सरकार से की जाएगी।

12. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के User's Guide to Procurement of works के Sectopn-4 Bidding Forms के अंतर्गत Bill of Qualities में पृष्ठ संख्या 61-62 पर दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजना में Provisional Sum का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग कालांतर में निम्नलिखित कार्यों में या आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य कार्य में किया जा सकेगा (अनुलग्नक-4 पर संलग्न) -

- क) जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार रुक्का में इंटेक के निकट गेटलसुद डैम के De-silting कार्य के लिए।
- ख) भूमिगत जलाशय की गहराई बढ़ाने हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने के लिए।
- ग) निर्माण स्थल पर Abandoned निवासों को तोड़ने के लिए।
- घ) Distribution Network को properly position करने हेतु Utility Shifting के लिए।
- च) सड़कों एवं जलमीनारों की आवश्यकतानुसार मरम्मत के लिए।
- छ) एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के Safeguard Policy Statement-2009 के आलोक में प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजना के लिए बने Resettlement & Rehabilitation Budget के आवंटन के लिए।

13. एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतर्गत JUJIP अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक परियोजनाओं हेतु जुड़को लि० के स्तर पर आवश्यकतानुसार पृथक बैंक खाता संधारित किया जाना है। उक्त के आलोक में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत प्रस्तावित परियोजना हेतु बैंक खाता संधारित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार राशि हस्तांतरित की जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन के क्रम में बैंक खाते में संधारित राशि का उपयोग संबंधित परियोजना के विपत्र के भुगतान हेतु किया जाएगा।
14. उक्त के आलोक में विपत्रों के भुगतान के पश्चात claim form CAAA (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को समर्पित किया जाएगा। DEA की स्वीकृति के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा व्यय की गई कुल राशि का 70% (ADB Share राशि प्रतिपूर्ति स्वरूप राज्य सरकार को आवंटित की जाएगी।
15. उपरोक्त परियोजना के निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंडों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी भूमि झारखंड सरकार की है, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने हेतु संबंधित विभाग को अधियाचना भेजी जा चुकी है।
16. उक्त परियोजना हेतु निविदा प्रकाशन जुड़को लि०, राँची के स्तर से किया जाएगा। निविदा अंतर्राष्ट्रीय खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया (International open competitive bidding) के तहत आमंत्रित की जाएंगी। जुड़को लि० द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य को ससमय निष्पादन कर कार्य आवंटित किया जाएगा।
17. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि के स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन कंडिका-11 में उल्लिखित परियोजना मद से किया जाएगा।
18. परियोजना हेतु प्रस्तावित वितरण नेटवर्क (Distribution Network) की रुपरेखा को केन्द्रीय रुपांकन संगठन (CDO), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड के द्वारा परीक्षणोपरांत स्वीकृति प्रदान की गई है।
19. कंडिका-8 में अंकित DPR की कुल प्राक्कलित राशि 75266.22 लाख रु० की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग से प्राप्त है।
20. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-
 - क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
 - ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
 - ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charge) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-Mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।
 - घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
21. प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन 36 माह में पूर्ण करना निर्धारित है।

22. उपरोक्त कंडिका 1-21 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है-
- क) राँची शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 43349.10 लाख रु० एवं परिचालन तथा रख-रखाव की राशि (OPEX) 31917.12 लाख रु० अर्थात् कुल परियोजना लागत राशि 75266.22 लाख रु० को प्रशासनिक स्वीकृति।
- ख) उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार तैयार किए गए Standard Bid Document एवं इसके उपयोग की स्वीकृति।
- ग) उपरोक्त कंडिका 9-11 में वर्णित परियोजना के वित्तपोषण प्रस्ताव पर स्वीकृति।
23. प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक-25.02.2019 को संपन्न बैठक में इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है कि जलमिनारों को यथासंभव सम्प से परिवर्तित किया जाएगा एवं कम से कम जलमिनारों का निर्माण कराया जाएगा।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति के उक्त शर्त का यथासंभव अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
24. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 01.03.2019 को संपन्न बैठक में मद संख्या 31 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

ह०/-

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(अनुसूचित - 1)

F.No.5/12/2017-ADB.I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
[Multilateral Institutions Division]

Room No.161A, North Block, New Delhi,
Date: December 08, 2017

To,

Mr. Kenichi Yokoyama
Country Director
Asian Development Bank,
India Resident Mission,
4 San Martin Marg
Chanakyapuri, New Delhi

Subject: Proposed Jharkhand Urban Infrastructure Investment Programme (JUIMP) for external assistance from ADB-regarding.

During the 77th meeting of the Screening Committee of DEA held on November 21, 2017 at North Block, New Delhi, a project proposal of Government of Jharkhand titled "Jharkhand Urban Infrastructure Investment Programme" was considered. The Committee decided to recommend the proposal for financial assistance of US\$ 458million from ADB to be provided in two tranches. Relevant extracts of the minutes of the Screening Committee meeting are enclosed.

2. Department of Economic Affairs hereby poses the said project to ADB for financial assistance as per the recommendations of the Screening Committee. ADB is requested to take further necessary action in this regard.

Encl.: As above

Yours sincerely,



(Jai Kishore)

Under Secretary to the Government of India
Tel.: 2309 3743
E-mail: kishore.jai@nic.in

Copy to:

1. Sh. Amit Khare, Additional Chief Secretary, Planning-cum-Finance Department, Jharkhand, Ranchi. E-mail : jhar.fin.sec@gmail.com
2. Sh. Arun Kumar Singh, Principal Secretary, UD & HD, Government of Jharkhand, 4th Floor, Project Building, Dhurwa, Ranchi. Email: ud.secy@gmail.com
3. Sh. Sunil Kumar Pal, US (UD-III), Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi. Email: sunilkr.pal@nic.in

6.6 The Screening Committee approved the project in principle subject to submission of revised PPR by the Deptt. of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Incorporating suggestions as mentioned above.

7. Jharkhand Urban Infrastructure Investment Program (JUIP)

7.1 Shri Arun Kumar Singh, Principal Secretary, UD & HD, Government of Jharkhand made a presentation before the Screening Committee and sought a financial assistance of US \$ 458 million for the JUIP (total cost being \$ 654 million). The financial assistance of US \$ 458 million has been sought in two tranches of \$ 295 million and \$ 163 million respectively (to be firmed up during the project preparation phase).

7.2 The project proposal seeks to provide sustainable water supply, septage, collection and disposal and sewerage infrastructure with improved services across the State. It will involve expansion of existing water supply distribution, reuse of treated sewage and for conservation of water, improved transportation facility in the towns and cities, and enhanced social infrastructure facilities.

7.3 JS (MI), DEA enquired about the finance plus elements of the project, and how the engagement of ADB would help the project beyond the need for finance. Principal Secretary explained that the project would benefit from ADB's national and international experience of sustainable financing for water supply and waste water management projects. Apart from strengthening ULBs, there would also be a scope to develop and implement innovative financing mechanisms with ADB's assistance. He further explained that the Project would improve the quality of life in the cities by creating sustainable water supply & sewerage and improved transportation facilities. It was further informed that finance plus elements would include adopting ADB's success stories in various cities of South Asia in providing 24x7 sustainable water supply, strengthening of institutional capacity of various departments in ULBs, inclusive economic growth including job creation, new technology for micro-tunnelling and creation of assets under the project, etc. JS (MI) advised the project authority to send a detailed information on finance plus elements (which has since been received).

7.4 On an inquiry about land issues, Principal Secretary, UD that there are no land related issues which could adversely impact the project.

7.5 After detailed deliberation, the Screening Committee approved the project proposal under reference for financial assistance from ADB of US \$458 million to be provided in two tranches (Tranche-1: US \$ 295 million and Tranche-2: US \$ 163 million).

(अनुसूची - 2 (3))

Project Administration Instructions

PAI 3.03
13 August 2014

INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING

A. Introduction

1. International competitive bidding (ICB) is the most appropriate method of procurement under ADB financing in most cases. This provides an executing agency¹ with a wide choice in selecting the best bid from competing suppliers and contractors. It gives prospective bidders from eligible source countries equal opportunity to bid on goods and works² that are being procured under ADB financing. The flow charts in Appendix 1 of this project administration instruction (PAI) show the main steps for procurement under ICB, including review and approval procedures.

2. The financing agreement usually provides that procurement under the project must follow ADB Procurement Guidelines. The borrower³ and its executing agency must follow the recommended procedures in preparing prequalification, bidding, and contract documents; advertising bid invitations; and accepting, opening, and evaluating bids. These procedures, their requirements, and relevant issues arising are discussed in this PAI and in PAI 3.09.

B. Price Thresholds for International Competitive Bidding

3. ICB procedures are normally employed for contracts with estimated values that exceed thresholds set at the time of procurement plan preparation. The current range of ICB thresholds for ADB borrowers is a minimum of \$3 million and a maximum of \$40⁴ million for works contracts or a minimum of \$1.0 million and a maximum of \$10 million for supplying goods depending on the assessed performance of contractors/suppliers in the market. These ICB thresholds also represent contract amount ceilings for national competitive bidding (NCB) and are normally stated in the procurement plan except when some contracts have yet to be specified as in sector projects. For the current thresholds by country, ADB staff administering projects shall refer to Appendix 2 or consult with the Operations Services and Financial Management Department (OSFMD) for the latest values.

C. Packaging International Competitive Bidding Contracts

4. Whenever possible, procurement should be such that each bid package or contract is large enough to be suitable for ICB. The size and scope of individual contracts will depend on the magnitude, nature, and location of the project. The objective in determining contract packages is to divide the requirements of the project into a manageable number of appropriate contract packages that will produce the maximum competitive response from bidders. To do this for goods procurement, the nature and value of the goods grouped into each contract package and the conditions of the potential market of supply must be understood. For works, homogeneous contract sections or buildings or other physical facilities need to be determined and assessed against the capabilities of local contractors and the perceived level of interest of foreign contractors. The capacity of an executing agency to administer the contracts may also affect the choice of contract type. Contract packaging is concluded during project processing by agreement between the executing agency and ADB. The contract packages and methods of procurement

¹ Includes implementing agency for the rest of this PAI

² "Goods and works" include related services such as transportation, insurance, installation, and commissioning, training and initial maintenance.

³ Includes grant recipient for the rest of this PAI.

⁴ The "\$" values may refer to equivalents in other currencies.

ICB THRESHOLDS

Table 1: Thresholds for Works (and Plant)

Threshold	DMC	Remarks
\$ 3 million	BHU, CAM, COO, FIJ, FSM, KGZ, KIR, LAO, MLD, MYA, NAU, PAL, RMI, SAM, SOL, TAJ, TIM, TKM, TON, TUV, VAN	To be reviewed during the CPS preparation. At other times thresholds may be adjusted if justified by a market assessment.
\$ 5 million	AFG, ARM, AZE, GEO, MON, NEP, PNG, UZB	
\$ 10 million	KAZ, VIE	
\$ 15 million	BAN, PAK, PHI, SRI	
\$ 25 million	INO, MAL, THA	
\$40 million	IND, PRC	

Table 2: Thresholds for Goods

Threshold	DMC	Remarks
\$ 1 million	BHU, CAM, COO, FIJ, FSM, GEO, KGZ, KIR, LAO, MLD, MYA, NAU, PAL, RMI, SAM, SOL, TIM, TKM, TON, TUV, VAN	Subject to assessment during project processing
\$ 2 million	AFG, ARM, AZE, BAN, KAZ, MON, NEP, PNG, SRI, TAJ, UZB	
\$2 to \$5 million ¹	INO, MAL, PAK, PHI, THA, VIE	
\$3 to \$10 million ¹	IND, PRC	

¹ In setting the specific ICB threshold for a project, staff shall consider the assessment of the supply market, including the interest of foreign suppliers. For example, the procurement of IT software is likely to attract international firms even for relatively small contract amounts. On the other hand, the procurement of basic school furniture is usually packaged into fairly large contract amounts but will not be attractive to foreign suppliers.

(अनुलग्नक - 3)



HANDBOOK
ON
PROJECT PREPARATION AND LOAN NEGOTIATIONS

GUIDELINES FOR
PROJECT PREPARATION AND LOAN NEGOTIATIONS WITH
MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS (MDBs)

June 2011

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

Pg 1 of 2



Asian Development Bank

(अनुलग्नक - 2 A)

India Resident Mission

23 August 2013

Mr. Nilaya Mitash
Joint Secretary (MI)
Department of Economic Affairs (DEA)
Ministry of Finance
New Delhi.

Dear Mr. Mitash,

Re: Increase of ICB Works Threshold for India

We are pleased to inform you that ADB has approved the increase of the international competitive bidding (ICB) threshold, or national competitive bidding (NCB) contract ceiling for civil works contract in India, from \$10 million to \$40 million, effective immediately for new projects and new procurement activities under ongoing projects.

We are copying this letter to all Project Directors for immediate application of the new threshold.

Sincerely,

Hun Kim
Country Director *lss*

Cc: Mr. Puneet Agarwal, Director (ADB), DEA
Ms. Sumita Singh, Deputy Secretary (ADB-II), DEA
All Project Directors

4 San Martin Marg, Chanakyapuri
New Delhi 110021, India

Tel +91 11 2410 7200
Fax +91 11 2687 0955

adb.inrm@adb.org
www.adb.org/inrm

Pg 1 of 1

(अनुसूची - 4)

USER'S GUIDE TO PROCUREMENT OF WORKS

ASIAN DEVELOPMENT BANK

June 2018

ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB

Pg 1 of 4

Ministry/State Governments understand this early on in the Government's budget cycle so that adequate provision is made in the budget for the year the project is likely to become effective and also in future years of implementation.

16. **Costing:** Costing is an important issue which EAs have to keep in mind. Apart from specifications, costing is also linked to different types of procurement. ICB or NCB and the kind of procedures it takes would have an element of cost attached that EAs need to be aware of. During designing, the technical requirements in procurement as per MDB procedures need to be clearly brought out, discussed and firmed up. Safeguard requirements also have a costing element. In using NCB as a method of procurement, care should be taken to ensure agreement is reached with MDB by Appraisal Stage / fact-finding stage itself, concerning local regime as applicable and MDB's requirements. (See paragraph below)
17. **Procurement:** The different methods of procurement as per MDB policy are important to be highlighted to the Executing Agencies. The requirements under International Competitive Bidding, National Competitive Bidding, Shopping, etc., should be discussed at length. It is important that the EAs and the Line Ministry/State Government understand the procurement procedures and documents thoroughly. They should also be made aware of implications of mis-procurement.
18. On the World Bank side, model bidding documents for NCB have been agreed with GoI Task Force. For NCB these documents need to be used. These need to be clearly understood by the EAs during the preparation stages itself.
19. On the ADB side, there has been some flexibility in redesigning the NCB documents. Both EAs and Team Leaders can be advised to start discussing procurement related issues right from the beginning. This would entail that existing bid documents in a particular sector or in different State in that sector or some State sector may be shared and thoroughly discussed so as to address all issues. Separately, in consultation with DEA, ADB could also start the process of having discussions on procurements in a generic way with each State at the level of Finance and Planning Departments. Such an approach would benefit both sides in allowing operations to proceed as per existing practice without breach of procedure or time. Simultaneously, they would also allow standardization of templates on a State basis keeping in mind sectoral requirements.
20. For ICBs, the standard bidding documents of the MDB needs to be used. Wherever applicable, this must be explained to the EAs and the Line Ministry/State Governments.
21. In addition the EAs and Line Ministry/State Governments must familiarise themselves with the applicable procurement guidelines of the MDB which are available at their websites.

Bill of Quantities

Objectives

The objectives of the Bill of Quantities are the following:

- (a) to provide sufficient information on the quantities of Works to be performed to enable bids to be prepared efficiently and accurately; and
- (b) when a contract has been entered into, to provide a priced Bill of Quantities for use in the periodic valuation of Works executed.

To attain these objectives, Works should be itemized in the Bill of Quantities in sufficient detail to distinguish between the different classes of Works; or between Works of the same nature carried out in different locations or in other circumstances that may give rise to different considerations of cost. Consistent with these requirements, the layout and content of the Bill of Quantities should be as simple and brief as possible.

Content

The Bill of Quantities should be divided generally into the following sections:

- (a) Preamble,
- (b) Work Items (grouped into parts),
- (c) Daywork Schedule, and
- (d) Summary.

Preamble

The Preamble should indicate the inclusiveness of the unit prices, and should state the methods of measurement that have been adopted in the preparation of the Bill of Quantities and that are to be used for the measurement of any part of the Works.

Rock

Where excavation, boring, or driving is included in the Works, a comprehensive definition of rock (always a contentious topic in contract administration), if not given in the Technical Specification, should be given in the Preamble, and this definition should be used for the purposes of measurement and payment.

Work Items

The items in the Bill of Quantities should be grouped into sections to distinguish between those parts of the Works, which by nature, location, access, timing, or any other special characteristics, may give rise to different methods of construction, phasing of the Works, or considerations of cost. General items common to all parts of the Works may be grouped as a separate section in the Bill of Quantities. When families of Price Adjustment formulas are used, they should relate to appropriate sections in the Bill of Quantities.

Quantities

Quantities should be computed net from the Drawings, unless directed otherwise in the Contract, and no allowance should be made for bulking, shrinkage, or waste. Quantities should be rounded up or down where appropriate, and spurious accuracy should be avoided.

Units of Measurement

The following units of measurement and abbreviations are recommended for use unless other national units are mandatory in the country of the Employer.

Unit	Abbreviation	Unit	Abbreviation
cubic meter	m ³ or cu m	metric ton (1,000 kg)	t
hectare	ha	millimeter	mm
hour	h	month	mon
kilogram	kg	number	nr
kilowatt	kW	square meter	m ² or sq m
lump sum	sum	square millimeter	mm ² or sq mm
meter	m	week	wk

Ground and Excavation Levels

The commencing surface should be identified in the description of each item for work involving excavation, boring, or driving, for which the commencing surface is not also the original surface. The excavated surface should be identified in the description of each item for work involving excavation for which the excavated surface is not also the final surface. The depths of work should be measured from the commencing surface to the excavated surface, as defined.

Daywork Schedule

- A Daywork Schedule should be included if the probability of unforeseen work, outside the items included in the Bill of Quantities, is relatively high. To facilitate checking by the Employer of the realism of rates quoted by the Bidders, the Daywork Schedule should normally comprise: a list of the various classes of labor, materials, and Contractor's Equipment for which basic Daywork rates or prices are to be inserted by the Bidder, together with a statement of the conditions under which the Contractor will be paid for work executed on a Daywork basis; and
- a percentage to be entered by the Bidder against each basic Daywork Subtotal amount for labor, materials, and plant representing the Contractor's profit, overheads, supervision, and other charges.

Provisional Quantities and Sums

Provision for quantity contingencies in any particular item or class of work with a high expectation of quantity overrun should be made by entering specific "Provisional Quantities" or "Provisional Items" in the Bill of Quantities, and not by increasing the quantities for that item or class of work beyond those of the work normally expected to be required. To the extent not covered above, a general provision for physical contingencies (quantity overruns)

should be made by including a "Provisional Sum" in the Summary of the Bill of Quantities. Similarly, a contingency allowance for possible price increases should be provided as a "Provisional Sum" in the Summary of the Bill of Quantities. The inclusion of such Provisional Sums often facilitates budgetary approval by avoiding the need to request periodic supplementary approvals as future needs arise.

The estimated cost of specialized work to be carried out, or of special goods to be supplied, by a Nominated Subcontractor should be indicated in the relevant part of the Bill of Quantities as a particular Provisional Sum with an appropriate brief description. A separate bidding procedure is normally carried out by the Employer to select the specialists, who are then nominated as Subcontractors to the main or prime contractor. To provide an element of competition among the main Bidders (or prime contractors) in respect of any facilities, amenities, attendance, etc., to be provided by the successful Bidder as prime contractor for the use and convenience of the specialist or nominated Subcontractor, each related Provisional Sum should be followed by an item in the Bill of Quantities inviting a percentage (to be quoted by the main Bidder) payable on the actual expenditure from the Provisional Sum.

Summary

The Summary should contain a tabulation of the separate parts of the Bill of Quantities carried forward, with provisional sums for Daywork, for physical (quantity) contingencies, and for price contingencies (upward price adjustment) where applicable.

Pg 4 of 4

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।